

• आम बजट में आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा खर्च • डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कई बड़े ऐलान
सबके विकास पर जोर

कॉर्पोरेट सेक्टर

15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर की दर एक और वर्ष के लिए मार्च, 2024 तक जारी रहेगी नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए।

▲ कोर्पोरेट जारी के लिए 10% का दर

पांच बड़ी घोषणाएं



कोकोबिस



मिथाइल एल्कोहल



एसिटिक एसिड

क्या हुआ महंगा



कृत्रिम जैलरी

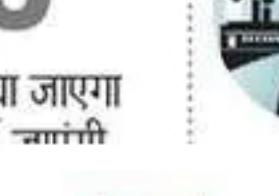


हेडफोन



इलेक्ट्रॉनिक खिलौने

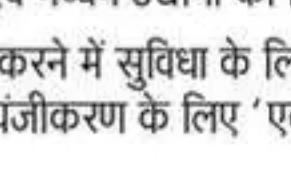
क्या हुआ सस्ता



तराशे गए हीरे



कैमरा लेंस



हीना

व्यापारी

00

न किया जाएगा



06

हजार करोड़ रुपये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलेंगे

• व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र,

युवा



60 लाख नौकरियां मेक इन इंडिया

के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी

• 14 क्षेत्रों से शुरू हुई उत्पादन से जुड़ी

प्रोत्ताहन योजना का दायरा बढ़ेगा,

शिक्षा



200

टीवी चैनल खोले जाएंगे पीएम ई विद्या के

'वन वलास, वन टीवी चैनल' योजना में



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था। • एनआई

02/02/2022

फीसदी का योगदान नेशनल पेशन स्कीम में दे सकेंगे राज्यों के भी कर्मचारी, पहले यह 10 था जबकि केंद्र के कर्मियों के लिए

यह पहले से 14 है। एनपीएस में योगदान कर कूट दिलाता है।

• कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 कर दर को घटाकर 15 करने का ऐलान, सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया।

• व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा।

• उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। एक करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को अतिरिक्त कर्ज।

• 14 क्षेत्रों से शुरू हुई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्ताहन योजना का दायरा बढ़ेगा, इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे।

• एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स में रोजगार की संभावनाएं। टारक फोर्स बनाकर काम होगा।

• स्टार्टअप को कर में मिली कूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी, इससे युवा स्टार्टअप के लिए प्रेरित होंगे।

• सभी राज्यों में कक्षा एक से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा।

• विज्ञान एवं गणित में 750 वर्षुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

कर्मचारी

14

फीसदी का योगदान नेशनल

सकेंगे राज्यों के भी कर्मचारी,

जबकि केंद्र के कर्मियों के

लाख करोड़ का बजट पेश किया सीतारमण ने, पिछले

साल से 4.61 लाख करोड़ ज्यादा

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने

के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि

सरकार बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च

करने जा रही है ताकि रोजगार के मौके सुविधा के लिए देश में

राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों

का जाल बिछाने के लिए 36 फीसदी ज्यादा रकम दी गई है। वहाँ,

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में भी 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की

गई है।

वित्त मंत्री ने करोबारियों को कुछ नए कर्ज, बच्चों की पढ़ाई,

सेवाओं के डिजिटल स्वरूप में विस्तार, महिलाओं के पोषण की

व्यवस्था, मिशन मेक इन इंडिया के तहत नौकरियां, पीएलआई

स्कीम में अतिरिक्त रकम और नई ट्रेनों का भी ऐलान किया।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाने की

घोषणा की।

वित्त मंत्री ने कहा, 'हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और

25 साल बाद हम इंडिया100 का जश्न मनाएंगे, यह बजट अगले

25 साल में अर्थव्यवस्था की बुनियाद तैयार करेगा।' मध्य कर्ज को

कोई राहत नहीं दिए जाने के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि

कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने दो साल से कोई कर नहीं

बढ़ाया है। हमने कर बढ़ाकर पैसे जुटाने की कोशिश नहीं की।

हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र के दौर में लोगों पर कर का बोझ

बढ़े। बजट में किसानों-व्यापारियों पर खासा ध्यान दिया गया है।